

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं अध्यक्ष राजस्व लोक अदालत न्याय आपकें द्वारा-2017

ग्राम पंचायत आलनिया, तहसील लाहुरा, जिला कोटा

पीठाधीन अधिकारी- श्री मोहनलाल प्रतिहार, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 25 / 15

श्रीमती अंजुमन कादरी पत्नी खुरशीद जालि मुखलमान निवासी खैलजगपुरा तहसील

लाहुरा, जिला कोटा

बनाम

1. राजस्थान राज्य जय तहसीलदार लाहुरा, जिला कोटा

2. नगर विकास न्यास कोटा

(वादीगण)

(प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92A राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

निर्णय

दिनांक : 17.05.2017



राज्य सरकार की ओर से संचालित न्याय आपकें द्वारा 2017 अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम पंचायत आलनिया के अदल सेवा केन्द्र में आयोजित राजस्व लोक अदालत में पंचावली पेश हुई। राजस्व लोक अदालत में उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। वादीगण की ओर से पेश किये गये वाद पत्र के अनुसार वादीनी ग्राम खैलजगपुरा तहसील लाहुरा जिला कोटा में निवास करती है और आराजी खसरा बनाकर काबिल है। वादीनी उक्त खसरा नम्बरान पर काबिल है और समय समय पर वादीनी को नो 56 रकबा 0.60 हेक्टर मूंस पर वादीनी काफ़ी समय से निवास कर रही है और पत्थर का कोट अन्सार वादीनी ग्राम खैलजगपुरा तहसील लाहुरा जिला कोटा में निवास करती है और आराजी खसरा विगत कड़े वर्षों से काबिल रहने के बावजूद भी तहसीलदार लाहुरा द्वारा उक्त खसरा नो 56 रकबा 0.60 मूंस को बिना वादीनी की सुनवाई के उक्त मूंस को राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित धारा-92 लैण्ड रेन्स्यू एक्ट के आगल की जा चुकी है, लेकिन उक्त आराजीयात पर वादीनी का आज भी कब्जा जारी है। इसके बावत मरे पक्षकारान मुखारानामा इरफान कादरी द्वारा धारा 80 सीपीसी का नोटिस भी दिया गया था। उसकी समय सीमा समाप्त होने के पश्चात उक्त वाद प्रस्तुत करना पडा है। वादीनी का बिना सुने व बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बदखल भी नहीं किया जा सकता और उक्त कृत्य को कर्ण कर देना वादीनी को दिलवाड़ जावे।

वादीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में निम्न दस्तावेजात पेश किये गये -

1	ग्राम खैलजगपुरा, तहसील लाहुरा के खाला नो नया 1 की नकल जमाबन्दी संवत 2073-2076
2	नकल खसरा परिवर्तन ग्राम खैलजगपुरा संवत 2057 वर्ष 2000-01, संवत 2060 वर्ष 2003-04, संवत 2061 वर्ष 2004-05, संवत 2058 वर्ष 2001-02 आराजी खसरा नो 56
3	तहसीलदार लाहुरा जिला कोटा द्वारा जारी मूंस-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अधीन नोटिस की कोटप्रति कूल 3- प्रकरण सं 478/2000, प्रोसो 1647/2000, प्रोसो 794/2002

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, कोटा
न्याय आणके द्वारा-2017
राजस्व लोक अदालत
कैम्प-आलोनिया



निर्णय में द्वारा आज दिनांक 17.05.2017 को ग्राम आलोनिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में न्याय आणके द्वारा 2017 अभियान के अन्तर्गत आयोजित राजस्व लोक अदालत में सुनाया गया।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर वादीगण को मात्र लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारी प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से खातेदारी अधिकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। इसी पर्या पृथक से जारी किया गया।

1	केवल लम्बे कब्जे के आधार पर वाद नहीं लाया जा सकता है। (परमसुख बंनारम स्टेट 1978, आर.आर.जी. 482)
2	किस्ती व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। (रामसिंह बंनारम पतिराम, 1996 आर.आर.जी. 389 पृज 391)
3	केवल मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। (राजस्थान राज्य बंनारम निरधारालाल, 1988 आर.आर.जी. 78)

इसने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का गुणावगण के आधार पर आलोचना अवलोकन अध्ययन किया, जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि विवादित आराजी पर वादीगण अपने कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार चाहते हैं। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित है, जिससे कृषि भूमि पर केवल कब्जे अथवा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। विधिसंगत तथ्य भी यही है कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी के अधिकार नहीं दिये जा सकते, चाहे कब्जा कितना भी लम्बा क्यों न हो। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालयों के गत निम्नांकित निर्णयों का भी दृष्टान्त लिया जाना समीचीन होगा -

वादी		जोड़	
1. वाद पत्र के लिये स्टाम्प	1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	2. अर्जी के लिये स्टाम्प	2. अर्जी के लिये स्टाम्प	2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. अदवायों के लिये स्टाम्प	3. एजीडर के लिये फीस	3. एजीडर के लिये फीस	3. एजीडर के लिये फीस
4. कपयों पर एजीडर की फीस	4. साक्षियों के लिये निर्वाह-व्यय	4. साक्षियों के लिये निर्वाह-व्यय	4. साक्षियों के लिये निर्वाह-व्यय
5. साक्षियों के लिये निर्वाह-व्यय	5. आदेशिका की तामिल	5. आदेशिका की तामिल	5. आदेशिका की तामिल
6. कम्प्लेन्स की फीस आदेशिका की तामिल	6. कम्प्लेन्स की फीस	6. कम्प्लेन्स की फीस	6. कम्प्लेन्स की फीस

वाद के खर्चे

उपरोक्त आदेशिका, कोटा
आर.ए.एस.

(महानलाल प्रतिहार)



गई।

यह डिक्री आज तारीख 17.05.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।
आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पूर्ण पृथक से जारी किया गया।
किये जा सकते हैं। अतः वाद वादिनी स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के लिये पेश होने पर वादिनी को मात्र लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खारिज आदेशिका प्रदान नहीं आदेशिका श्री महानलाल प्रतिहार, आर.ए.एस. (उपरोक्त आदेशिका, कोटा) के समक्ष अन्तिम निपटारे के अभिलेखों के आद्योपान्त अवलोकन उपरान्त आज तारीख 17-05-2017 को (डिक्रीदार) पीठासीन न्याय आपक द्वार-2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत आलनिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में आयोजित राजस्व लोक अदालत में पक्षकारान की सुनवाई एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त राजस्व

निर्णय दिनांक : 17.05.2017

सुकदमा नम्बर : 25/15

दावा बाबत : 88, 91, 92A RTA

(प्रतिवादीगण)

1. राजस्थान राज्य जय तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा
2. नगर विकास न्यास कोटा

बनाम

(वादीगण)

लाडपुरा, जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 25/15
श्रीमती अंजुमान कादरी पत्नी खुरशीद जालि मुसलमान निवासी खैलानापुरा तहसील

पीठासीन आदेशिका- श्री महानलाल प्रतिहार, R.A.S.
ग्राम पंचायत मोरपा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

न्यायालय उपरोक्त आदेशिका एवं अध्यक्ष राजस्व लोक अदालत न्याय आपक द्वार-2017
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

मूल वाद में डिक्री